प्रचार सभा, लेख, पत्रकार वार्ता आदि के लिए उपयुक्त मुद्दे :

- मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार गॉव, गरीब, सेना के जवान, नौजवान, किसान एवं मजदूरों को समर्पित है।
- इस देढ वर्ष में दलित, शोषित, पीड़ितों को न्याय देने के लिए और उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार ने कई कार्य किये हैं।
- मानवता के आधार पर पड़ोसी एवं अन्य देशों से सम्बन्ध मजबूत बनाये।
- सबसे बड़ी उपलब्धी यह है कि सरकार ने जनता का भरोसा जीता है।

प्रमुख उपलब्धियॉ

- पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा किये गये घनघोर भ्रष्टाचार के कारण कोयला, दूरसंचार, खनन, पर्यावरण, रक्षा, रेल, खेल, सड़क इत्यादि जैसे अनेक घोटाले हुए। देश की बदनामी हुई, तरक्की रूकी और अर्थव्यवस्था तथा रोजगार पर बुरा असर पड़ा।
- श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पारदर्शी नीतियॉ अपना कर इन सभी क्षेत्रों में अद्भूत सफलता प्राप्त की। कांग्रेस सरकार के काल में कोयले खदानों के आवंटन में 1.86 लाख करोड़ का नुकसान होने का अंदाज सीएजी ने लगाया था। हमारी सरकार ने 200 में से अनेक खदानों की नीलामी की और उससे लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक सरकारी खजाने में जमा हुए। इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के जमाने में पैसा सरकारी खजाने में जाने के बजाय कहॉ जाता होगा? सारा पैसा जहॉ खदाने हैं, उन्हीं राज्यों के विकास के लिए मुहईया कराने का एतिहासिक फैसला इस सरकार ने किया।
- 2–जी स्पेक्ट्रम का घोटाला भी कांग्रेस के कार्यकाल का काला अध्याय है। उसी स्पेक्ट्रम की नीलामी पारदर्शी तरीके से करके हमारी सरकार ने 1लाख 10 हजार करोड़ रूपये सरकारी खजाने में जमा किये।
- अन्य खनिजों के जेसै बक्साईट, मैंगनीज, लोह अयस्क, आदी खदानों का आवंटन भी अब नीलामी से करने का कानून पास हो गया। यह पैसा जनजाति क्षेत्र तथा राज्यों के विकास के लिए दिया जायेगा।

- विश्व स्तर पर समन्वय एवं सहमति प्राप्त कर **''21 जून''** को **''अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस''** दुनिया के 170 देशों में और भारत में हजारों स्थानों पर संपन्न हुआ।
- **''जन धन योजना''**, **''आम जनता के लिए विभिन्न बीमा येाजनाएं''**, **''स्वच्छ भारत अभियान''**, **''मेक इन इण्डिया''**, **''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ''**, **''डिजीटल इण्डिया''**, **''स्मार्ट सिटी योजना''**, **''सुकन्या समृद्धी योजना''**, **''हृदय–हेरिटेज सिटी योजना''**, **''अमृत–अरबन रिनिवल मिशन''**, **''आदर्श ग्राम योजना''**, **''मुद्रा बैंक''**, **''संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थय बीमा योजना''**, गैस सबसिडी बैंक में जमा करने वाली **''पहल''** योजना, **''इंद्रधनुष''** टीकाकरण योजना, **''स्वसत्यापन''** योजना, अल्पसंख्यक कौशल विकास **''उस्ताद''** योजना आदि नई योजनाओं का आगाज हुआ। इससे तरक्की की दिशा साफ हुई।
- व्यवसाय शुरू करने के लिए पहले 127 दिन लगते थे अब केवल 27 दिन में यह काम होने लगा।
- सेना के सेवानिवृत जवानों के लिए वन रेंक वन पेंशन की मॉग मंजूर की।

अर्थव्यवस्था पटरी पर :

- विरासत में जो अर्थव्यवस्था मिली उसमें भ्रष्टाचार, काले धन व आधारभूत ढांचे की कमी, बढ़ती मंहगाई, नीतियों के क्रियान्वयन में निश्चय का अभाव, बढ़ती बेरोजगारी, निवेशकों का खोया विश्वास आदि नकारात्मक विशेषताएं थी। उसे बदल कर नीतियों के आधार पर उसे सही रास्ते पर लाने का काम किया।
- 10 साल में न थमने वाली महंगाई कम हुई। थोक सूचकांक –2.33 तथा खुदरा सूचकांक 5 फिसदी के आसपास रहा। लोगों के लिए यह बड़ी राहत थी। पेट्रोल के दाम लगभग 7 रूपये और डीजल के दाम 6 रूपये तक कम हुए हैं। गेंहू, प्याज, दलहन पर आयात शुल्क हटाया। राज्यों के बीच बेरोकटोक आवाजाही की व्यवस्था की। जमाखोरी और कालाबाजारी रोक लगाई तथा चावल, उड़द और तुअर में फयूचर ट्रेडिंग बन्द किया।
- आयकर में छूट देते हुए अब कुल कटौती की सीमा 4लाख 44 हजार कर दी गई।
- पहले जीडीपी विकास की दर 5 फिसदी के नीचे थी अब एक साल में यह दर 7.4 तक बढ़ी। महंगाई जो 10 प्रतिशत से अधिक होती थी अब वह 5 फिसदी से नीचे आई है। वित्तीय घाटा व चालू खाते का घाटा कम हुआ है। बचत की दर बढ़ गई है। निवेषकों का खोया विश्वास वापस आया।

गरीब एवं श्रमिकों के लिए :

- गरीबों को आज तक सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं था। जन–धन योजना के तहत 19.21 करोड़ गरीबों के खाते बैंक में खुले, जिसमें उन्होंने 26,819 करोड़ रूपये स्वेच्छा से जमा भी किये। यह अपने आप में एक विश्व रिकार्ड है।
- प्रधानमंत्री जन–सुरक्षा बीमा योजना के तहत सालाना 12 रूपये भर कर 2 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा, सालाना 330 रूपये देकर 2 लाख रूपये का जीवन बीमा और प्रतिमाह 18 वर्ष की आयु से 210 रूपये भरने के बाद 60 साल के बाद जिन्दगी भर 5000 रूपये का मासिक पेंशन और अपने बाद पत्नी को वही पेंशन और दोनों के बाद उनके परिवार को 8.5 लाख रूपये देने वाली अटल पेंशन योजना यह गरीब को मिली जबरदस्त सामाजिक सुरक्षा है। इन योजनाओं में अब तक 11 करोड़ लोगों ने भाग लिया है।
- ईपीएस 95 योजना के तहत लाखों पेंशन धारकों को केवल प्रतिमाह 100–200 रूपये पेंशन मिलती थी। मोदी सरकार के एतिहासिक फैसलों के कारण अब ऐसे 24 लाख पेंशन धारकों कों न्यूनतम प्रतिमाह 1000 रूपये पेंशन मिलने लगी।
- यह सारा काम महज एक साल में हुआ। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। श्री मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की गरीबों के बारे में प्रतिबद्धता दर्शाती है।
- पेंशन धारियों के लिए तनखा की मर्यादा 7000 से बढाकर 21000 और बोनस की मर्यादा 3500 से 7000 तक बढाने का ऐतिहासिक फैसला किया। लोकसभा में बिल पारित भी हो गया है ।

काला धन के खिलाफ लड़ाई :

- काला धन के खिलाफ जबरदस्त कार्यवाही करते हुए मंत्री मण्डल की पहली बैठक में एसआईटी का गठन किया जो बहुत अच्छा काम कर रही है। 2012 में उच्चत्तम न्यायालय ने एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था, लेकिन कांग्रेस ने ढाई साल उसे टाला। जिस एसआईटी को कांग्रेस ने ढाई साल टाला था उसी को मोदी सरकार ने ढाई दिन में गठित कर के दिखाया।
- विदेश में काला धन रखने वालों को कड़ी सजा देने वाला बिल भी पास हो गया।
- जी 20 तथा अन्य देशों के साथ जानकारी के आदान–प्रदान की व्यवस्था कायम करने की बातचीत प्रारम्भ की है, जिससे कि विदेश में होने वाले अवैध आर्थिक गतिविधियों की जानकारी लगातार मिलती रहेगी और काले धन पर कार्यवाही की जा सकेगी।

किसानों के लिए :

- कांग्रेस सरकार ने डब्लूटीओ के मंच पर 2016 से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था लगभग खत्म करने की बात मान्य की थी। मोदी सरकार ने इस किसान विरोधी शर्त को मानने से विरोध किया। किसानों के लिये विश्व के मंच पर अकेले जोरदार लड़ाई की। इसके कारण किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का भारत के अधिकार को सभी देशों ने स्वीकार किया।
- किसान की गरीबी तभी दूर होगी जब खेती की उत्पादकता बढ़ेगी। आज दुनिया के औसतन फसल पैदावार की तुलना में हमारे यहॉ हर एकड़ में आधा ही उत्पादन होता है। जब तक जमीन की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी तब तक पैदावार और उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। इसलिए 14 करोड़ किसानों को ''**सॉइल हैल्थ कार्ड''** दिया जायेगा और यह देने का काम शुरू भी हो गया है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसान की मांग पर इस वर्ष भी दामों में बढ़ोत्तरी की।
- 2015 में असमायिक वर्षा और ओले के कारण किसानों को बहुत परेशानी हुई। आज तक जो व्यवस्था थी उसमें आसमायिक वर्षा तथा ओलावृष्टि को आपदा नहीं माना जाता था। हमारी सरकार ने इन संकटों को आपदा माना है और इससे आहत हुए किसानों के मुआवजे को डेढ़ गुना बढ़ाया है।
- पहले जिन किसानों का 50 प्रतिशत से अधिक फसल का आपदा से नुकसान होता था उन्हीं को मुआवजा मिलता था अब जिन किसानों का 30 प्रतिशत भी फसल नुकसान होगा वो मुआवजे के अधिकारी होंगे।
- अतिवृष्टि से खराब हुए टूटे और कम क्वालिटी के अनाज को कांग्रेस की सरकार के समय खरीदा भी नहीं जाता था तथा उसे कम दाम दिया जाता था। मोदी सरकार ने ऐसे अनाजों की भी कीमतें कम न करने का ऐतिहासिक फैसला लिया।
- किसानों के लिए बैकों से 8लाख 50 हजार करोड़ का रिकार्ड कर्जा मिलेगा, जिससे कि किसान को साहूकार के दरवाजे पर जाना नहीं पड़ेगा।
- किसानों को फसल सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए कोल्ड चेन की शुरूआत करने का फैसला मोदी सरकार ने लिया हैं।
- सरकार '**फूड मैप ऑफ इंडिया**'तैयार करवा रही है। **सॉईल हेल्थ कार्ड** बनाने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। 650 करोड़ खर्च कर 14 करोड़ किसानों को सॉईल हेल्थ कार्ड प्रदान किया जायेगा।

- 17 नए वृहत ''**फूड पार्कों**'' के निर्माण की योजना बनाई है, जिसमें से 2 का उद्घाटन भी हो चुका है। इससे 1 लाख लोगों को रोजगार तथा 5 लाख किसानों को आर्थिक फायदा पहुँचेगा।
  कृषि को समर्पित डीडी किसान चैनल शुरू हो गया है।
- देशी नस्ल की गायों के लिए ''**गोकुल मिशन**'' की शुरूआत की है।
- यूरिया की उपलब्धा बढ़ाने के तथा कालाबाजारी रोकने के लिए नीमलेपीत यूरिया वितरित किया जा रहा है। इससे चोरी और कालाबाजारी रूक गयी। कम यूरिया में अधिक फसल पैदा होने लगी।
- गोरखपुर, बडगाम, तालचेर तथा रामगुंडम में बन्द पड़े खाद कारखाने फिर से शुरू हो रहे हैं।
- गन्ना किसानों का हित सुरक्षित करने के लिए चीनी की आयात पर 40 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया है। ईथोनॉल पर एक्साइज कम किया गया है।
- किसान के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत 5300 करोड़ का प्रावधान किया है।
- इस वर्ष कपास की सबसे अधिक खरीद की गई है। किसानों की तकलीफों को ध्यान में रखकर कपास की खरीद के लिए अलग से 2500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मजदूर :

- मजदूरों को अधिक अधिकार देने के लिए 45 करोड़ मजदूरों को **''स्मार्ट कार्ड''** प्रदान करना शुरू हो गया है।इस स्मार्ट कार्ड में वृद्धावस्था पेंशन योजना, आम आदमी बीमा योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के लाभ मिलेंगे।
- कामगारों को जॉब बदलने पर पीएफ खाता ट्रॉसफर होने में और मिलने में भी दिक्कत होती थी। अब एक युनिक पीएफ नम्बर दिया जायेगा उससे आसानी से खाता ट्रॉसफर भी होगा और आसानी से रकम भी मिलेगी।

रोजगार :

- गरीब खेतिहर मजदूरों के लिए मनरेगा का बजट में प्रावधान बढ़ाकर 40 हजार करोड़ किया गया है। पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए गांवों में छोटे तालाब तथा छोटे बॉध बनाने का काम भी अब रोजगार योजना के तहत स्वीकृत है।

- छोटे एवं लघु उद्योगों के लिए 500 ''**इन्क्यूबेसन सेन्टर''** जिसमें उनको ऑफिस, कनैक्टिविटी और अन्य सहायता मिलेगी, जिससे शुरूआत में उनकी लागत बचेगी। ऐसे 15 केन्द्र साल भर में शुरू हुए हैं।
- खादी ग्रामोद्योग के **प्रधानमंत्री रोजगार योजना** में सहायता राशि डेढ़ गुना बढ़ाई है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
- मात्र 8 महिनों के अन्दर 20 ''**टेक्सटाईल पार्को**'' के निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनसे लगभग 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
- उत्तरपूर्व के 7 राज्यों में से 4 जगह **''एपैरल ट्रेनिंग सेंटर''** के माध्यम से 7 हजार नए रोजगारों का निर्माण किया गया।
- एनटीसी की 16 मिलों को नुकसान से बाहर निकाल कर उनको मुनाफे में पहुंचाया है।
- नये ई–रिक्शा कानून के तहत 1 लाख से ज्यादे ई–रिक्शाओं के परिचालन की अनूमति दी है। इससे लाखों रोजगार निर्माण होंगे।
- केन्द्रीय सुरक्षा बलों में कई वर्षों के पश्चात् लगभग 63,000 भर्तियॉ की जा रही हैं।
- 70 लाख लोगों को व्यवसाय के लिए बिना गैरंटी मुद्रा योजना में 46 हजार करोड़ रूपये मिले है।

ग्रामीण एव आधारभूत संरचना :

- 50000 किलोमीटर की ग्राम सड़क बनाने के लिए मजबूत वित्तीय प्रावधान किया गया। खराब सड़कों को दुरूस्त करना, उन्नत करना तथा चौड़ा करने के लिए समयबद्ध योजना की शुरूआत हुई है। इस काम के लिए बजट में 14 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- 8 हजार किलोमीटर के महामार्गों का निर्माण शुरू हुआ। जहॉ कॉग्रेस सरकार के समय प्रतिदिन 2 किलोमीटर सड़क बन रही थी, अब वहॉ अब रोज 18 किमी बन रही हैं। अनेक सड़क परियोजना बन्द पड़ीं थीं हमनें 80 रूके हुए कामों को दुबारा शुरू करवाया है।
- 5500 किलामीटर के बार्डर रोड बनाने का काम शुरू हो गया है
- जिला मुख्यालयों को राष्टीय महामार्गो तक जोडनेवाली सडक भी महामार्ग की तरह ही बनेगी ।
- ग्रामीण यातायात को बढ़ावा देने के लिए नदियों में 101 इनलैंड वाटर वेज बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए एक कानून भी बन रहा है।

- आदर्श गॉव के सपने को साकार करने हेतु गॉव के लिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधायें सुनिश्चित करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम जैसी अभूतपूर्व योजना के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को प्रत्येक वर्ष सीधे एक ग्राम से जुड़ने से प्रेरित कर के ग्रामीण व्यवस्था के उत्थान का प्रयास किया जा रहा है।
- **''स्वच्छ भारत अभियान''** के द्वारा सफाई को एक जन अभियान बनाया गया है। इसके द्वारा जन–जन को परिसर एवं खुद को स्वच्छ रखने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी फायदों के बारे में बताया गया।
- 7 साल में **''सबके लिए आवास''** योजना के तहत 4 करोड़ ग्रामीण एवं 2 करोड़ शहरी घर विहीन परिवारों को आवास की सुविधा देन की योजना मंजूर हो गई है।
- 100 **''स्मार्ट सिटी''** बनाने की योजना, **''अमृत''** शहरी नवीकरण की योजना तथा ऐतिहासिक धरोहर वाले शहरों के संरक्षण–संवर्धन की योजना **''हृदय''** अपने वृहत स्तर पर प्रगतिशील है।
- सरकार ने 136 सीमेंट उत्पादकों के साथ एमओयू करके सस्ते से सस्ते दाम पर सीमेंट की उपलब्धता आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्यों के लिए सुनिश्चित की।
- **''सागरमाला''** योजना के तहत भारत के तटीय क्षेत्रों में अनेक नए बन्दरगाहों के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया है।
- 8 हजार किमी के नए मार्गों पर और पुरानी 80 प्रतिशत सड़क योजनाओं पर कार्य द्रुत गति से प्रारम्भ है।

समाज कल्याण :

- हाथ से मैला ढुलाई करने वालों को इस अभिशाप से मुक्त करने के लिए मात्र एक साल में 2500 लोगों को इस व्यवस्था से निकाल कर प्रति व्यक्ति लगभग 40 हजार रूपये खर्च करके उन्हें अन्य व्यवसाय में लगाने के लिए उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ–साथ इनको 1500 से लेकर 3000 रूपये तक का मासिक भत्ता प्रशिक्षण के दौरान दिया जा रहा है।
- इस अभिशाप से मुक्त हुई 250 महिला सफाई कर्मचारियों को ड्राईविंग का प्रशिक्षण दिया गया है।
- दलित छात्रों के स्कालरशिप की रकम में वृद्धि की गई है।
- **भारत रत्न डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर का भव्य स्मारक** मुम्बई में स्थापित करने के लिए इंदूमिल की जगह दी गई है।

- 192 करोड़ की लागत से भारत रत्न **बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर के नाम से एक विश्व स्तर के संस्थान** का शिलान्यास हाल ही में मा0 प्रधानमंत्री जी ने किया है।
- **बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर** के 125वें जयन्ती समारोह के उपलक्ष में प्रधानमंत्री ने 125 रूपये और दस रूपये के सिक्के आने वाली पीढ़ियों के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में आम जनता के लिए जारी किए।
- दलित युवाओं को उद्योग लगाने को उतप्रेरित करने के लिए **200 करोड़ का उद्यमिता विकास फंड** और **200 करोड़ का वैनचर कैप्टल फंड** का प्रावधान किया है।
- शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों को मोटर लगी हुई साईकिल उपलब्ध कराई गयी है।
- **घूमन्तु जातीय समुदाय** जो अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग में कहीं भी नहीं आ पाते उनको चिन्हीत कर उन्हें इनके अन्तर्गत लाने हेतु **एक आयोग का गठन किया गया है।**
- यह आयोग इन घूमन्तू जातीय समुदायों तक **पूर्व मैट्रिक–उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधा** इत्यादि पहुॅचाने की दिशा में प्रयास शुरू कर चुका है।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरूआत। उनके लिए भवन–मार्ग, परिवहन एवं सूचना तकनीक हर स्तर पर सुविधाजनक बनेगा।
- प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में निःशक्त जनों के परिपेक्ष में **विकलांग की बजाय दिव्यांग शब्द** के उपयोग करने का सबसे आहवाहन किया।
- लन्दन में जिस घर में बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने रहकर शिक्षा प्राप्त की, उस घर को खरीद कर सरकार ने उनके स्मारक एवं शोध संस्थान में परिवर्तित कर दिया है। इसका उद्घाटन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री ने वहॉ जाकर किया।

जनजाति कल्याण :

- जनजातियों को वन से मिलने वाले गौण वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त था। अब पहली बार सरकार ने जनजातियों का इन **गौण वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य** देने का निर्णय किया है और इसके लिए अलग से 10 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया है।
- जनजाति बन्धुओं को वनोपज की बिक्री एवं सही कीमत के बारे में जानकारी देने के लिए **मुफ्त कॉल सेन्टर** की सुविधा भी उपलब्ध करायी गई है।

- इन्जीनियरिंग, मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेने वाले **अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों** की संख्या बढ़ गई है, इसलिए अब इन्जीनियरिंग, मेडिकल संस्थानों में **इनके कोटे की सीटें** खाली नहीं जा रही हैं।
- जनजाति क्षेत्रों में जरूरी वृहत आधारभूत संरचना के विकास हेतु **''वन बन्धू कल्याण योजना''** के अंतर्गत 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।
- नये 41**''एकलव्य मॉडल रेजिडेंसियल विद्यालय''** महज एक साल में खोले हैं। अब नवोदय विद्यालय की तर्ज पर चलने वाले इन स्कूलों की **संख्या 84 से बढ़कर 115** हो गई है।

बेटी :

- भ्रूण हत्या रोकने के लिए बेटियों के लिए **''बेटी बचाओं – बेटी पढ़ाओ''** जैसी महत्वाकांक्षी दूरगामी परिणामों वाली योजना शुरू की गई है।
- भ्रूणहत्या को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया गया है।
- सुकन्या योजना शुरू की गई है। बेटी के जन्म के बाद 1000 रूपये जमा करके यह खाता खुल जायेगा। बेटी के 21 साल की होने पर उसमें जो भी रकम जमा होगी, सरकार उस राशि पर ब्याज समेत कई गुना रकम उस बेटी को देगी।
- बेटियों की पढ़ाई मुफ्त होगी उनके लिए स्कूलों में बड़े पैमाने पर शौचालय बनाने का काम शुरू हो गया है। बच्चों में अब पहले के मुकाबले कुपोषण में 10 प्रतिशत की कमी आई है।
- महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। जिसमें **''एसिड अटैक'' की घटनाओं की रोकथाम** के लिए कानून में संशोधन, पीड़ित महिलाओं के उपचार एवं पुनर्वसन की सुविधा और उन्हें अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए **''केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा फण्ड''** बनाया जा रहा है।
- जुविनाईल जस्टीस बिल पारित किया है जिससे जघन्य अपराध करनेवाले 16 साल से अधिक आयु वाले बालकों को भी संरक्षण नहीं मिलेगा।
- इसके अतिरिक्त, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को रोकने लिए देश के 150 जिलों में अन्वेषण ईकाई स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग हेतु 150 जिलों में अन्वेषण ईकाई स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग हेतु एक नई योजना बनायी गई है।
- पुलिस में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू।

- दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ''**हिम्मत**'' नामक मोबाईल एप की शुरूआत की गई।

गृह एवं रक्षा क्षेत्र :

- सीमा प्रबंधन में चुस्ती मुस्तैदी दिखाते हुए बाड़ लगाने, सुरक्षा बलों की तैनाती, जवाबी क्षमता एवं उनको मिलने वाली सुविधा में बड़े बदलाव किये हैं। **सीमायें अधिक सुरक्षित।**
- हुद–हुद तुफान एवं बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में आये भूकम्प और जम्मू कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थिति में **एनडीआरएफ एवं सुरक्षा बलों की त्वरित कार्यवाही** के बलबूते अधिसंख्य आपदा ग्रस्त लोगों को तुरन्त सहायता पहुंचाई जा सकी।
- जिस कोसी नदी के बाढ़ से उत्तर बिहार में प्रत्येक वर्ष हजारों लोग तबाह एवं विस्थापित हो जाते थे। इस साल बाढ़ की आशंका के समय ही **नेपाल के साथ संपर्क कर कुशल व्यवस्था प्रबंधन के द्वारा हजारों लोगों को बाढ़ के संकट** से बचाया गया।
- महाराष्ट्र में हुए भू–स्खलन, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में आए साइक्लोन ''**हुद–हुद**'' (3.9 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया) तथा आसाम, मेघालय एवं जम्मू और कश्मीर (2.9 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया) में आई बाढ़ आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई।
- चैन्नई में आई बाढ की आपदा में सैनिक बल एवं एनडीआरएफ ने लोगों को राहत पहुचांई
- आपदा में मृतक के आश्रित को दी जाने वाली सहायता राशि को दोगुने से भी ज्यादा बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है।
- 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के आश्रित को अतिरिक्त मुआवजे की स्वीकृति दी गई है। दंगों की पुनर्जांच के लिए जस्टिस जी.पी. माथुर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है।
- वर्ष 2014 में 671 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया जबकि यह संख्या वर्ष 2013 में मात्र 282 थी। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं एवं मृतकों की संख्या में वर्ष 2013 की तुलना में 2014 में 22 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई।

- **36 राफेल लड़ाकू विमानों की सीधी खरीद** कर वायु सेना की क्षमता को मजबूती प्रदान की।
- भारत में ही सुरक्षा एवं सैन्य सामग्री निर्माण करने की नीति को प्राथमिकता दी है।
- देश में सामाजिक सदभाव मजबूत हुआ है और माओवादी कार्यवाहियों पर भी सभी संबंधित राज्यों से सलाह मशवरा करके काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने माओवादियों से हिंसा का रास्ता त्यागने की अपील भी की है।
- **पर्सन्स ऑफ इंडियन कार्ड को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के साथ एकीकृत** कर अब उनके धारकों को और अधिक सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं।
- **जवानों का मनोबल ऊँचा** करने के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं, जैसे कि चिकित्सकीय उपचार अवधि को कार्यावधि माने जाने संबंधी आदेश राशन भत्ते में बढ़ोतरी इत्यादि।
- पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में उन राष्ट्रों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए लांग टर्म वीजा और नागरिकता संबंधी मामलों पर विचार के लिए टास्क फोर्स का गठन।
- कश्मीरी युवकों को समुचित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए **''उड़ान''** योजना के तहत विशेष प्रयास करते हुए मई, 2014 से जनवरी, 2015 तक 16 विशेष अभियान चलाए गए जिसमें 9 हजार युवकों का चयन किया गया।

उत्तर–पूर्व राज्य

- अलगाववादी गुट एनएससीएन (आई.एम.) के साथ ऐतिहासिक संरचनात्मक समझौता किया।
- पहली बार **पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में रोटेशनल सचिवालय** की व्यवस्था की गई है। यानि कि प्रत्येक माह इनमें से एक राज्य से उत्तरपूर्वीय क्षेत्र विकास मंत्रालय 4 से 5 दिनों के लिए अपना सारा कामकाज करेगा।
- **अब उत्तरपूर्व के 8 राज्यों में हर 15 दिनों में एक केन्द्रीय मंत्री का भ्रमण होता है ।**
- उत्तरपूर्व से संपर्क में सुधार लाते हुए कोहिमा तक की सीधी फ्लाईट और गोहाटी व मेघालय के बीच में रेल सुविधा की शुरूआत की गई।
- मेघालय एवं अरूणाचल प्रदेश को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ा गया और पूरे पूर्वोत्तर के सातों प्रदेशों में 1000 किमी. से ज्यादा सड़क योजना पर काम चल रहा है।
- पहले से उपलब्ध 12 एफएम चैनलों के अलावा 18 नए एफएम चैनल पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए खोले गए तथा अरूण प्रभा करके पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेषकर अलग से 24X7 चैनल खोला गया।

- असाम में नया एम्स खोला गया तथा पूर्वोत्तर भारत की खेल संस्कृति को ध्यान में रखकर एक विशेष खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में खोलने की योजना।
- पूर्वोत्तर भारत के मेधावी छात्रों के लिए एक अलग से ईशान उदय करके छात्रवृति योजना चालू की तथा एक विशेष बीपीओ स्कीम के तहत 5000 से ज्यादा कॉल सेन्टर सीटों का रोजगार प्रारम्भ करने की योजना।

पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते :

- 26 मई 2014 को सरकार के शपथ ग्रहण में सार्क देशों पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव आदि देशों के प्रमुख उपस्थित हुए और मोदी जी नेतृत्व में आस्था जताई।
- नेपाल में भयंकर भूचाल के बाद भारत ने **''ऑपरेशन मैत्री''** चंद घटों में मदद पहुचाना शुरू किया और पीड़ितों को सहायता करने का बड़े पैमाने पर कार्य किया। जिसकी सराहना पूरे विश्व ने की। मालदीव में पीने के पानी का भयंकर संकट अचानक निर्माण हुआ। भारत ने हवाई जहाज एवं समुद्री जहाज से पानी की आपूर्ती की ।
- श्रीलंका के साथ संबंधों में सुधार लाया और पकड़े गये और सजा पाये भारतीय मछुआरों को रिहा करवाया।
- बांग्लादेश के साथ 40 साल से चल रहे सीमा विवाद खत्म करके एक एतिहासिक समझौता साकार किया। इससे दोनों देशों के सम्बन्ध अच्छे हुए, पूर्वोत्तर राज्यों से सम्पर्क आसान होगा और सीमा सुरक्षा चुस्त होगी।
- इराक में फंसी अनेक भारतीय नर्स, लीबिया तथा यमन में फसे 4,741 भारतीयों को और 48 अन्य देशों के 1947 फंसे हुए नागरिकों की सुरक्षित वापसी करने का ऑपरेशन राहत अत्यधिक सफल रहा एवं विश्व ने उसको सराहा।
- अफगानिस्तान में भारत ने संसद भवन बनाया जिसका उदघाटन प्रधानमंत्री जी ने किया

अन्य देशों के साथ संबंध :

- दुनिया के सभी देशों के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं। अमरीका, ब्राजील, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जर्मन, फ्रॉस, चीन, मंगोलिया, श्रीलंका, भूटान, कोरिया, नेपाल, जापान, म्यांमार, फिजी, सैशल्स, मॉरिशस, सिंगापुर ईगलैण्ड, रशिया, अफगानिस्तान,

पाकिस्तान, तुर्कीस्तान आदी देशों में प्रधानमंत्री की अत्यन्त सफल यात्राएं हुईं, जिसके कारण भारत की प्रतिमा विश्व के मंच पर साकारत्मक रूप से बदली है।

- विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी की अनेक देशों में यात्राएं भी हुईं और सभी प्रमुख सम्मेलनों में उन्होंने भारत का पक्ष मजबूती से रखा इसलिए भारत का स्थान विश्व में और मजबूत हुआ है।

स्वास्थ्य :

- 90 लाख बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गये थे। उनके लिए टीके लगाने के लिए मिशन ''**इंद्रधनुष**'' नाम से एक कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है और अब तक इसके तहत 25 लाख बच्चों का टीकाकरण हो चुका है।
- ''**स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत**'' कार्यक्रम के तहत अस्पतालों के बीच स्वच्छ से स्वच्छ रखने की प्रतिस्पर्धा के माध्यम से स्वच्छता की भावना जगाई।
- पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में नये ''**एम्स**'' खुल गये हैं।
- 500 से ज्यादा जरूरी जीवन रक्षक दवाओं को ड्रग प्राईस कन्ट्रोल प्रक्रिया के अन्दर लाया है, जिससे उनकी कीमत में 5 से 40 प्रतिशत तक की कमी आई।
- फार्मा जन समाधान की व्यवस्था की है।
- 80 लाख शौचालयों का निर्माण पुरा हुआ है।

शिक्षा :

- पहली एवं दूसरी, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ''**पढ़े भारत, बढ़े भारत**'' की शुरूआत।
- ''**सर्व शिक्षा अभियान**'' को सही मायने में सुधार कर जनता के सामने रखा इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। स्कूलों में पर्याप्त कमरे शौचालयों तथा पानी के लिए वित्तिय प्रावधान पहली प्राथमिकता मानकर किया गया है।
- ''**स्वयं**'' योजना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता का डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन परीक्षा की व्यवस्था की गई है। जोकि आईआईटी एवं आईआईएम जैसे उच्च गुणवत्ता के केन्द्रों से दी जाऐगी। इसकी परीक्षा के लिए 500 केन्द्रों की व्यवस्था की है।
- '**ज्ञान**' नाम की योजना के अंतर्गत विदेशों से सैकड़ों प्राध्यापकों को बुलाकर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए सार्थक पहल होगी।

- **''ई–लाईब्रेरी''** के द्वारा पीएचडी के थिसिस तथा आईआईटी, आईआईएम और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लाईब्रेरियों को पोर्टल पर सामुदायिक किया जायेगा। अब लाईब्रेरी की सुविधा सभी को कम्प्यूटर पर प्राप्त होगी।
- देश के सभी सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री के आहवाहन पर लड़के–लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है।

रेल :

- रेलवे नेटवर्क के चौमुखी विकास की योजना के लिए 1 लाख करोड़ रूपये दिये गये हैं।
- इसमें से 40 हजार करोड़ बजट में प्रावधान, 30 हजार करोड़ एलआईसी से तथा 30 हजार करोड़ रेलवे के आंतरिक स्त्रोंतों से होगी।
- इस रकम से रेलवे की नई आधारभूत संरचना मजबूत की जायेगी तथा यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा बढ़ाने का कार्य शुरू हो गया है।
- रेल को समय पर चलाने के लिए दोहरीकरण, तिहरीकरण तथा विस्तार के काम शुरू कर दिये गये हैं। रेल में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए के लिए सार्थक कदम भी उठाए गये हैं।
- मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए जापान से विशेष समझौता हो गया है ।

रोजगार :

- लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 500 सेंटर खोलने की योजना में से 15 अबतक खुल गये हैं। पीएमजीईपी योजना में डेढ़ गुना वित्तीय प्रावधान किया गया है। इससे लाखों युवाओं को उद्योग शुरू करने के लिए पैसा अब मुहैया कराया जा सकेगा।
- पहले पान की दुकान, नाई की दुकान, बेकरी की दुकान, सब्जी की दुकान, परचून की दुकान इत्यादि जैसे छोटे व्यवसायीओं को व्यवसाय के लिए जरूरी धन आसानी से लोन पर नहीं मिल पाता था। अब इन छोटे वयवसायियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ''**मुद्रा बैंक''** की स्थापना की गई है। जिससे उन्हें अब 10 हजार से 10 लाख तक का ऋण आसानी से मिल पायेगा।
- बेरोजगार युवाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु ''**स्फूर्ति**'' नाम से एक नई योजना के द्वारा 70 नए पारम्परिक कौशल प्रशिक्षण के केन्द्र विगत मात्र एक वर्षों में खोल कर इस

सरकार ने बेरोजगार युवाओं के स्वर्णिम भविष्य निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की है।

- कुल 500 स्थानों पर छोटे–छोटे उद्योगों को एकीकृत सुविधा पहुॅचाने के लिए 500 इनक्यूबेसन सेंटर खड़े करने की योजना बनाई है, जिसमें से 15 सेन्टर ने काम करना भी शुरू कर दिया है।
- **पीएमजीइपी योजना** के अंतर्गत कुल रकम का प्रावधान डेढ़ गुना बढ़ाया है।
- कॉइर उद्योग विकास की योजना को भी मूर्त रूप दे दिया गया है।
- **प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन** केन्द्र के माध्यम से प्रत्येक जिले में 3 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है।
- राष्ट्रीय कौशल मिशन के अंतर्गत कौशल विकास नीति का निर्धारण किया गया है। अब ''**स्कूल से स्किल(कौशल)''**यानि कि 12वीं कक्षा पास करने के साथ–साथ कौशल की योग्यता का भी प्रमाण–पत्र अब दिया जा रहा है।

अल्पसंख्यक कल्याण :

- ''**उस्ताद**'' नाम की एक अनूठी योजना के माध्यम से पारम्परिक कौशल के विकास एवं संरक्षण की मुहिम चालू है।
- इसके अलावा मदरसे में पढ़ने वाले किशोरों को **''सीखो और कमाओ''** योजना के तहत वित्तीय सहायता और कौशल सीखाने के साथ–साथ उनके लिए संगठित और असंगठित क्षेत्र में शत प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित किया।
- 6 महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदायों के इतिहास और विरासत के संरक्षण का काम इस सरकार ने किया है।
- सरकार ने एक और कदम उठाते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के 1 करोड़ बच्चों को मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति देने का सराहनीय प्रयास शुरू कर दिया है।
- योजना के तहत अल्पसंख्यकों के लिए सामुदायिक भवन, पाठशाला, पुस्तकालय, शौचालय आदि सुविधा का विकास सरकार ने शुरू कर दिया है।
- सरकार ने वक्फ की सम्पत्ति का सामुदायिक कार्यों के लिए उपयोग करने का बड़ा निर्णय लिया है।
- **''साइबर ग्राम''** योजना के तहत सरकारी स्कूल एवं मदरसों के क्षात्रों को कम्प्यूटर एवं डिजिटल ज्ञान की सुविधा प्रदान की।

पारदर्शिता :

- कांग्रेस के शासनकाल में जो कोयला एवं दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता की वकालत हमने की थी उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमने कांग्रेस के जमाने के 200 रद्द खदानों में से 33 की पारदर्शी तरीके से नीलामी कर सरकारी खजाने में 2 लाख करोड़ रूपये जमा करवाए, जिसका उपयोग अब जनता के हित में विभिन्न कल्याणकारी कार्यों में होगा।
- दूरसंचार विभाग के द्वारा भी स्पेक्ट्रम नीलामी में ऐसी ही पारदर्शिता का परिचय देते हुए सरकारी कोष को 1लाख 10 हजार करोड़ रूपये का फायदा पहुंचाया जोकि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2जी घोटाले में बंदरबॉट किये गये रकम के लगभग बराबर की धनराशि है।
- **'पहल'** योजना के तहत 12.5 करोड़ लोगों को उनकी एलपीजी सबसिडी की रकम सीधे उनके खाते में पहुँचाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है।
- पर्यावरण की मंजूरी के लिए ''**ऑनलाईन प्रकिया**'' शुरू कर दी गई है।
- 892 पुराने अनावश्यक कानूनों को सरकार ने समाप्त करने का प्रभावशाली स्पष्ट कदम उठाया। साथ ही साथ **''अपना हस्ताक्षर अपना प्रमाण''** जैसे स्व–सत्यापन के स्वभाविक कदम तुरन्त उठाये।
- जिस घरेलू उत्पादित गैसों का मूल्य कांग्रेस की सरकार ने 4.20 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से बढ़ाकर 8.40 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू करने का फैसला किया था और लोक सभा चुनावों के दौरान प्रचार में भी यह मुददा उठा। हमारी सरकार ने उसी गैस की कीमत को वैज्ञानिक फामूले के तहत 8.4 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से घटाकर 5.6 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू कर दिया है। इसको सारी दुनिया ने सराहा।
- ग्रुप डी एवं सी स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति में साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म की गयी तथा ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड पदों पर भी साक्षात्कार खत्म करने की पहल।

पर्यावरण की रक्षा :

- वनीकरण के लिए प्रस्तावित **''कैम्पा''** कानून के तहत राज्यों को 38 हजार करोड़ रूपये देने के लिए बिल संसद में पेश किया है।
- अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 3200 उद्योगों के दूषित पानी एवं दूषित वायु की नए तकनीक के आधार पर 24 घंटे निगरानी रखने की ऑनलाईन व्यवस्था की गयी है।

- **इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट, कनस्ट्रक्शन वेस्ट** एवं **अत्यंत हानिकारक कचरों** के संयोजन के लिए नए नियम बना दिये गये हैं जो जनवरी से लागू होंगे।
- भारत के सीमीवर्ती क्षेत्रों में 6 हजार किमी सड़कों के निर्माण को सामान्य स्वीकृति दी गई।
- दुनिया के सबसे ज्यादा **बाघ** अब भारत में हैं और उनकी संख्या **2226** हो गई है।
- पहले राज्यों के सार्वजनिक उपयोग के प्रकल्पों के मंजूरी में भेदभाव होता था। हमारी सरकार ने यह कुप्रथा बन्द की और सभी राज्यों के जनहित के प्रकल्पों को पर्यावरण रक्षा की शर्तो के साथ मान्यता दी गई।
- **2–3–4 पहिये वाले इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों को 30 प्रतिशत की सबसिडी** दी गई है और इसके लिए 14 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 60 हजार करोड़ के ईधन की बचत होगी।
- दिल्ली के प्रदूषण को मात देने के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान एवं सभी संबंधित नगर निकायों को साथ लेकर एक साल का एक्शन प्लॉन तैयार किया है।

विकेन्द्रीकरण :

- **14वें वित्त आयोग की सिफारिश** को मानते हुए केन्द्रीय आयकर में **राज्यों का हिस्सा अभूतपूर्व ढंग से 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत** कर राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की है। इससे राज्यों को 2 लाख करोड़ रूपये अधिक मिले हैं।
- 33 कोयला ब्लाकों के आवंटन से न केवल केन्द्र सरकार को 2 लाख करोड़ की आय हुई बल्कि राज्यों के लिए भी अगले 30 वर्षों में 1.41 लाख की रॉयल्टी सुनिश्चित हो गई।
- क्षेत्रीय परिषदों और स्थायी समितियों की बैठकें, जो वर्षों से लंबित थीं, की गई हैं। इससे केन्द्र एवं राज्यों के संबंधों में प्रगाढ़ता आई है और कई मुद्दों को आपसी सहमति से हल किया गया है।

पर्यटन :

- पर्यटकों के लिए ''**ई–टूरिस्ट वीजा स्कीम'' प्रारंभ** की गई। इस स्कीम के तहत अब तक 74 देशों को सम्मिलित किया गया है। इब तक 1,15,000 से अधिक लोगों को

वीजा जारी किया जा चुका है। इस कदम से देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

- ऐतिहासिक दर्शनीय धरोहर स्थलों पर ई–टिकटिंग की व्यवस्था।
- पर्यटकों की सुविधा के लिए 24 घंटे की 12 भाषाओं की सुरक्षा हेतु एक **हेल्पलाईन नम्बर 1363** शुरू की है।

सूचना प्रद्योगिकी, संचार तथा डाक :

- **82 करोड़ लोगों को यूआईडी आधार कार्ड** से जोड़ा।
- महज एक वर्ष के अन्तराल में बीएसएनएल मोबाईल सेवा की सिग्नल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 25 हजार मोबाईल टावर लगाने की योजना है, जिसमें से **15 हजार नए मोबाईल टावर** लग चुके हैं और शेष कार्य प्रगति पर हैं।
- 30 वर्षों से अधिक पुराने 432 टेलीफोन एक्सचेंजेस और 70 लाख नई लाईनों को नेक्सट जनरेशन नेटवर्क (NGN) से परिवर्तित करने का कार्य प्रगति पर है। जिससे उपभोक्ताओं को वीडियो कॉलिग जैसी आधुनिक सुविधाएँ प्राप्त हो पाऐंगी।
- इंटरनेट की सबके लिए एक जैसी न्यूट्रल व्यवस्था यानी की **नेट न्यूट्रलिटी बरकार** रखने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है।
- इलेक्ट्रानिक उत्पादन बढ़ाने के लिए 6 हजार करोड़ मंजूर।
- **21 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर** मंजूर। इससे हजारों रोजगार तैयार होंगे।
- **छोटे शहरों में 48 हजार सीट के कॉल सेन्टर** लगाये जायेंगे जिससे लाखों रोजगार तैयार होंगे। पूर्वोत्तर राज्य में कॉल सेन्टर के लिए विशेष योजना स्वीकृत की है।
- डाक विभाग ई–कामर्स में अधिक सक्रियता से काम कर रहा है।
- **''डिजिटल इण्डिया योजना''** के तहत 2 लाख 50 हजार गॉव में ब्रॉड बैण्ड की सुविधा देने के कार्यक्रम के अमल में तेजी से तरक्की हो रही है।
- पेंशनधारियों के लिए पहले जीवित रहने का प्रमाण हर साल में जाकर देना पड़ता था, अब **''जीवन प्रमाण'' की नई व्यवस्था** से यह दिक्कत दूर हुई है, जिसका लाभ अब तक 1 लाख 75 हजार धारक उठा चुके हैं।
- साथ ही डिजीटल लॉकर, ई–बस्ता, ई–हॉस्पिटल और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर वाई–फाई लगाने की योजना प्रगति पर है।
- केन्द्र द्वारा अनुदानित सभी प्रकार की छात्रवृति योजनाओं के लिए अब एक राष्ट्रीय छात्रवृति वेब पटल, जहॉ से अब विभिन्न छात्रवृतियों के लिए एकीकृत रजिस्ट्रेशन और वितरण की व्यवस्था की गई है।

- सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में डॉक्टरों के अपॉइन्टमेन्ट की अब ऑन–लाईन सुविधा शुरू की गई है।

युवा एवं खेल–कूद :

- 2016 एवं 2020 के ओलम्पिक को ध्यान में रखकर कुल 75 चुनिन्दा खिलाड़ियों को अत्याधुनिक ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार ने सुनिश्चित की है। इसके लिए आवश्यक उतना बजट मिलने की गारंटी।
- राष्ट्रीय युवा महोत्सव का सफल आयोजन गोवाहटी में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।
- **''नेशनल स्पोर्टस डवलेपमेंट कोड''** लागू किया।
- खिलाड़ियों के **खुराक भत्ते में बढ़ौत्तरी।**

विज्ञान, तकनीकि एवं भारी उद्योग :

- **मंगलयान मिशन** में ऐतिहासिक सफलता।
- दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन 1230 करोड़ लागत से लग रही है। इसमें भारत बड़ी भागीदारी कर रहा है।
- नेशनल सुपर कम्प्यूटिंग मिशन के तहत 45 सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
- **मौसम का पूर्वानुमान** सभी किसानों एवं तटीय क्षेत्र के मछुवारों को **मोबाईल पर एसएमएस एलर्ट के द्वारा** पहुँचाने की व्यवस्था की गई है।
- महिला वैज्ञानिकों को शोध कार्यों में प्रोत्साहन के लिए **''किरण''** नाम से एक नई योजना की शुरूआत की गई।
- अंटार्कटिका में रिमोट से चलने वाले देश में निर्मित वाहन स्थापित किये गये हैं तथा ध्रूवीय क्षेत्रों में शोध के लिए पोत लगाने के लिए 1050 करोड़ का प्रावधान किया है।
- 660 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल जनरैटर का निर्माण भेल द्वारा किया गया है।

गंगा एवं जल–संसाधन :

- ''**नमामि गंगे**'' कार्यक्रम के तहत गंगा की स्वच्छता और अविरलता पुनः स्थापित करने के लिए 27 हजार करोड़ रूपयों का एक अलग से कोश बनाया है।

- गंगा के तटीय इलाकों में स्थित **अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 764 औद्योगिक ईकाईयों को चिन्हीत** करके कड़े प्रावधानों द्वारा उनके उत्सर्जन को न केवल सीमित किया है बल्कि उनके **ऑनलाईन मानिटरिंग** की भी व्यवस्था की है।
- गंगा सफाई का अभियान जोरों–शोरों से चल रहा है और गंगा को प्रदूषण एवं कचरा मुक्त करने के लिए उसमें गिरने वाले शहरी नालों का उपचार एवं शोधन करके दूषित पानी को गंगा जल में मिलने से रोकने की सघन व्यवस्था की जा रही है।
- नदी में तैरते हुए कचरा एकत्रित करने की क्षमता रखने वाले अत्याधुनिक जहाज जैसे आधुनिक उपकरणों एवं वैज्ञानिक तरीकों का सरकार अब उपयोग गंगा की सफाई में कर रही है।
- सिर्फ 1 साल में नदियों को आपस में जोड़ने की कई योजनाओं को स्वीकृति दी है। जैसे नेपाल से बहने वाली काली एवं शारदा नदी पर **''पंचेश्वर इंटरलिंकिंग''** योजना की तहत काम शुरू हो गया है। इसी प्रकार केन और बेतवा एवं मुंबई में दमन गंगा और पिंजाल **नदियों पर भी इंटरलिंकिग** का काम चालू हो गया है।
- **''पोलावरम सिंचाई परियोजना''** को **राष्ट्रीय योजना** का दर्जा दिया।

विद्युत गैस एवं नविकरणीय उर्जा :

- **कोयले और बिजली का उत्पादन में रिकार्ड बढ़ौत्तरी** हुई।
- **अपारम्परिक सौर, पवन और जैविक उर्जा का लक्ष्य बढ़ा कर 1 लाख 75 हजार मेगावाट किया गया है।** यह दुनिया का **सबसे बड़ा हरित उर्जा का कार्यक्रम** है। निवेशकों ने भी जबरदस्त उत्साह से निवेश करने का वादा किया है।
- हमारी सरकार के आने से पहले लगभग **4 करोड़ घरेलू गैस सिलेण्डरों** की कालाबाजारी हो रही थी, इनकी हमने पहचान कर उनकी **कालाबाजारी रोकने में सफलता** हासिल की। पिछले वर्ष में 40 हजार करोड़ की लागत से बिजली का ट्रॉसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सुधार किया, **अगले 6 महिने में 1 लाख करोड़ का निवेश होगा।**
- देश भर में सड़क पर और घरों में करोड़ों एलईडी लैम्पस लगाने का कार्यक्रम शुरू हो गया।
- ''**दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना**'' के तहत सभी गॉवों को **24 घंटे बिजली पहॅुचाने के कार्यक्रम की शुरूआत**।
- ''**पहल**'' योजना के तहत **12.5 करोड़ लोगों के खाते में अब गैस सिलेण्डर** पर मिलने वाली **सबसिडी सीधे** पहॅुचती है।

- मा0 प्रधानमंत्री के आह्वाहन पर लगभग **3 लाख 70 हजार लोगों ने अपनी गैस पर मिलने वाली सबसिडी वापस कर दी** है। यह सबसिडी वाले कनैक्शन जिनके पास गैस नहीं है, उन्हें दिये जायेंगे।
- देश भर में करोडो एलईडी बल्ब जनता को केवल सौ रुपये में उपलब्ध कराये गये है।
- जहां बिजली नहीं पहुंची थी ऐसे 1800 गावों में बिजली पहुंचाई गयी।
- बिजली उत्पादन में जबरदस्त बढोतरी हुई है।

न्याय एवं विधि व्यवस्था :

- पूराने एवं **अनावश्यक 1700 कानूनों को समाप्त** कर दिया।
- राष्ट्रीय विधिक नीति का निर्माण किया जिसकी वजह से न्यायलयों में लगभग 40 प्रतिशत केसों में कमी आई ।
- **''राष्ट्रीय न्यायीक नियुक्ति आयोग''** बनाने का बिल पास होकर नोटिफाई भी हो गया है। इस बिल को लाने के लिए सभी राज्यों से हमने सहमति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।
- सभी **उच्च न्यायलयों में एक वाणिज्य खण्डपीठ** बनाने की व्यवस्था की है।

मेक इन इण्डिया :

- उद्योग को अपने जीवन चक्र के दौरान लाईसेन्स और नियन्त्रण मुक्त करना और तेज गति और पारदर्शिता के कदम शुरू हो गये।
- इंडस्ट्रियल कैरिडोर का काम गति से प्रारम्भ हो गया।
- उद्योग एवं व्यापार के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट स्वीकृति।
- देशी विदेशी निवेश को बढ़ावा।
- कौशल विकास और शोध को प्रोत्साहन।
- आयात निर्यात व्यापार की नई नीति जिसका सबने स्वागत किया।
- भारत को उत्पादन का केन्द्र बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास।
- छोटे निर्यातक और नए क्षेत्रों को ज्यादा सहायता।
- किसान और छोटे उद्योगों की रक्षा के लिए एंटी–डम्पींग डयूटी और आयात शुल्क का उपयोग।

नागरिक विमानन क्षेत्र :

- हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई।
- **पहली बार एयर इण्डिया कार्यकारी मुनाफे** में।
- नए हवाई अड्डों की योजना और पुराने हवाई अड्डों का एकिकरण।

****